भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केंद्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

30 जुलाइ 2022

जल–जगल–जमिन–इज्जत और सशक्तीकरण के लिए आदिवासी जनता के संघर्षों को ऊंछा रखे! 9 अगस्त अंतरष्ट्रीय दिवस को मनाए! आदिवासी जनता के उपर होनेवाली अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करें!

अगस्त 9 तारीख विश्व आदिवासी दिवस के मौके मे, नई वन सरक्षण नियम, जो केंद्र सरकार 2022 जून 28 तारीख को प्रस्तावित किया गया, उसके विरोध में, इसके साथ–साथ दण्ड़कारण्य और बिहार–झारखण्ड़ की आदिवासी जनता के संघर्षों का समर्थन मे विभिन कार्यक्रमों को आयोजित करने की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी आह्वान देती हैं।

ब्राह्मणीय हिदृत्वा फासिवादी भाजपा ने द्रौपदि मुरमू जो ओड़िशा राज्य में मयूरभंज जिला उपरबेडा गाव मे एक संथाली आदिवासी परिवार मे जन्म लिया, उनको भारत का राष्ट्रपति ऐसे समय में बनाया गया, जब देश के शासक वर्गों ने आदिवासी जनता के सघर्षों को समाप्त करने की प्रक्रिया में लगा हुओ है। और कउस जनता के उपर नरसंहार का दौर चला रहा हैं। अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषण के बाद भाजपा ने नई वन संरक्षण नियम कों अलोकतांत्रिक संविधान के खिलाफ लाया, जो 5वा और 6वी षेड्यूलों, संविधान, और इसके तहत पेसा कानून का घोर उल्लंघन करता हैं। अधिकरण 244 जो इस षेड्यूलों, कानूनों का अमल के लिये देश के राष्ट्रपति, और राज्यों का राज्यपालों को उपर उछस्तर जिम्मेदारी रखती है, यह कभी अमल मे नही आया है। आदिवासी जनता और उन के संघषों की उपर भाजपा दमन और नरसंहार का रवय्या अपना रहा हैं।

आदिवासी जनता पूरी हिम्मत से उन पुलीस केम्पों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, जो फिलाल मे ही झार्खण्ड राज्य का गिरिडिह जिला मे पर्वतपूर गाव के पास, छत्तीसगढ़ राज्य का बीजानूर–सुकमा जिलाओं मे सिलिंगेर और अन्य जगहों पर स्थापित हो रहा है। लोकतांत्रिक, क्रांतिकारी, और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व मे केंद्र, और राज्य सरकारों के खिलाफ संघर्ष जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की मिली घटित नीति के तहत आदिवासी जनता के जमीनों को उन से छीना जा रहा है। और ये प्रक्रिया देश के कई हिस्सों मे जैसे ओडिशा राज्य मे नियमगिरि मे, महाराष्ट्र का गढ़चिरोली जिला मे सूर्जागढ़, छत्तीसगढ़ मे नारायणपूर मे आमदाई मे, और झार्खण्ड मे अन्य जगहों मे आदिवासी जनता को उन के जमीनों से वंचित किया जा रहा है। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा साफ है, इस के जरिये भाजपा उपने नरसंहार को छुपाने के लिये एक अवश्यक जरिया मिला है। माओवादी पार्टी, जनता का सेना पीएलजीए, और जनता का राज्याधिकार अंग क्रांतिकारी जनता के कमेटीओं के उपर भाजपा एक के बाद एक दमन अभियान चला रहा है। और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को जड से मिठाने के लिये प्रयास मे लगा हुआ है। इस के सिवाय उच्छ न्यायालय को नियंत्रित करते हुये, इस के द्वारा सार्किनगुडा, एडसमेट्टा के नरसंहारों मे सरकारी सशस्त्र बल को निर्दोष साबित करने का ये षड्यंत्र रचा है। यहा तक की उच्छ न्यायालय अपने उच्छारण मे उन सभी लोगों जो आदिवासी जनता के हित के लिये और उन के तरफ से पिटिशन डाल रहे है, उने दण्डित किया जा रहा है। ठीक इसी तरह उन लोगों को भी सताया जा रहा है, जो पिटिशन द्वारा उच्छ न्यायालय को जनता विरोधी कार्यक्रम, और हिंसा, जो कुले आम हिंदुत्व के इसारे पे तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन पर रोक लगाने की प्रयास कर रहे है। ये साफ तौर से संविधान और न्याय व्यवस्था के उल्लंघन है। जन विरोधी केंद्र और राज्य सरकार की इच्छा यही है की, देश की आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक जनता को कोई भी मदत नही मिलना चाहिये। इस के लिये हिंदुत्वा ताकतो ने सारे पत्रिका, टीवी, सोषल मीडिया को अपने मुट्टि मे बंद कर लिया है।

ऐसे परिस्थिति मे जब ब्राह्णीय हिंदुत्वा फासीवाद तेजी से देश के हर कोने मे फैल रहा है, तब सारे उत्पीडित वर्गों, लोकतांत्रिक, बुद्धिजीविओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक ही मकसद होना चाहिये। वह है की निर्भय होके असली लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाने के लिये अपना आवाज बुलंद करना चाहिये। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ मे आदिवासी जनता का संघर्षों को गौरव से आगे ले जाने की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्र कमेटी आह्वान देती है। और ये भी स्पष्ट कर्ती है की सरकार को उन सारे जन विरोधी कानूनों को जो जनता के उपर शोषण का माहोल पैदा कर रहा है, उनहे वापस ले। केंद्र कमेटी आदिवासी जनता के उपर

हो रहे अत्याचारों को और उन से उन के जमीन से वंचित करने की प्रक्रिया जो चल रही है, उस का घोर खंडित और विरोध करने का आह्वान देती है। विश्व भर मे वन क्षेत्र मे नियंत्रण के लिये आदिवासी जनता के उपर होनेवाली शोषण को विरोध करते हुये उन के संघषों को मदत देनी की आह्वान कर्ती है।

अभय,
प्रवक्ता,
केंद्र कमेटी,
भाकपा (माओवादी)